Educationaly out of 45 districts, 24 districts have literacy below the State average of 43.5 per cent (1991 census). Industrially 40 out of 45 districts of State have been identified as backward. Out of these 36 have been declared as backward by Central Government and 4 districts by the State Government. Though successive Five Year Plans and Annual Plans the State Government has been making sincere efforts to remove regional imbalances within the State.

कृषि विकास की दर

4080. **श्री विनोद शर्मा :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एटथ प्लान प्लेमड एक्सरसाइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछली पंचवर्षीय योजना में यह वृद्धि 2.9 प्रतिशत तक थी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस वार्षिक वृद्धि दर से आगामी वर्षों में देश की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना संभव नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो वृद्धि दर का यह लक्ष्य किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आठवीं योजना (1992-97) के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास के लिए प्रस्तावित लक्ष्य 3.1 प्रतिशत प्रति वर्ष है । सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में, प्राप्त की गई वार्षिक औसत विकास दर 3.6 प्रतिशत बताई गई है ।

(घ) आठवीं योजना में दस्तावेजों में खाद्यान्नों का उत्पादन और आवश्यकता अनुमान 1996-97 के लिए क्रमश: 210 मिलियन टन और 208 मिलियन टन लगाया गया है ।

(ङ) कृषि क्षेत्र के लिए विकास दर, कृषि सहित अर्थ-व्यवस्था की समग्र विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित दर तथा सभी क्षेत्रों की अनुमानित की गई है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्राथमिकताएं

4081. **श्री विनोद शर्मा :**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए प्राथमिकतायें निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में किन-किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है; है ; और

(ग) इन प्राथमिकताओं का क्रम क्या है और इन क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशियों की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है और चालू योजनावधि के दौरान इन क्षेत्रों में कितने-कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने का निश्चय किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक

ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की निम्नलिखित प्राथमिकतायें हैं :—

(1) शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रोजगार का सृजन ।

(2) लोगों के सक्रिय सहयोग के जरिए जनसंख्या तथा नियंत्रण निवेश तथा अनिवेश की प्रभावी स्कीम ।

(3) सबको प्राथमिक शिक्षा तथा 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की निरक्षरता का पूर्णतः उन्मूलन ।

(4) सभी गांवों तथा समग्र जनसंख्या को सुलभ सुरक्षित पेयजल तथा प्रतिरक्षण सहित प्राथमिकता स्वास्थ्य देख रेख सुविधाओं का प्रावधान करना तथा मैला ढोने को पूर्णतः समाप्त करना ।

(5) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा निर्यात के लिए अधिशेष सृजित करने के लिए कृषि का विकास एवं विविधीकरण ।

(6) विकास प्रक्रिया को सतत आधार पर बनाए रखने में सहायता देने हेतु आधारिक संरचना (ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई) का सुदृढ़ीकरण ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान सभा पटल पर रखे गए आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज की ओर आकर्षित किया जाता है ।

Foreign financial aid to States for Development Projects

4082. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to give States the entire amount received as foreign financial aid through World Bodies for development projects; and

(b) what has been the practice in vouge so far in this regard and the details of changes to be effected by the decision referred to above?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKHRAM): (a) The Government have decided to give to the States, the entire amount received as credit or aid through multilateral or bilateral external agencies for development projects of the State Governments.

(b) Prior to this, 100 per cent external aid was passed on to the States only for social service sector programmes and programmes which have a direct bearing on poverty alleviation. In other sectors only 70 per cent was passed on to the States.

Development of backward areas in Eastern Uttar Pradesh

4083. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether any steps have been taken for the development of backward areas of the country particularly the eastern Uttar Pradesh;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) to (c) The responsibility for development of a particular region rests primarily with the State Government concerned. In this the Central Government helps the States, including Uttar Pradesh, through the mechanism of transfer of resources under revised formula, previously known as 'Gadgil Formula', Spe-